ECONOMICS

By
Mustafa Nawaz
Astt.Professor,LSW
Shershah College, Sasaram
Date: 19.02.2024

भारत में कृषि विकास :

भारत में कृषि विकास को चरणबद्ध रूप से समझा जा सकता है।भारत में कृषि विकास की रणनीति 1991 में लागू उदारीकरण के पूर्व प्रति कृषक उत्पादन रही थी, जबकि उदारीकरण के उपरांत प्रति कृषक शुद्ध आय रही है, ताकि भूमि की सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि हो सके।

संस्थागत सुधारों का चरण (1951-1966) :

- कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता
- कृषि और उद्योग के पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास
- मध्यस्थ की भूमिका समाप्त करने का प्रयास
- 1950 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन एवं भू-चकबंदी

तकनीकी सुधारों का चरण (1966-1976) :

- उच्च उत्पादकता वाले बीजों (HYVS) का प्रयोग

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग

- नई सिंचाई तकनीकों की व्यवस्था
- समेकित जिला कृषि कार्यक्रम
- कृषि में आधुनिक मशीनों का प्रयोग

एकीकृत विकास का चरण(1976-1991) :

- निर्धन समूहों की पहचान कर उनके लिए उत्पादक रोजगार का सृजन
- कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा
- वित की संस्थागत स्रोतों का सुदृढ़ीकरण
- सूखे तथा अकाल जैसे समस्याओं के लिए अतिरिक्त वितीय सहायता का प्रावधान
- कई विशिष्ट कार्यक्रम का आरंभ :-
- 1. MFAL- Marginal Farmers and Agriculture Labour Scheme
- 2.DPAP- Drought Prone Area Program

समेकित विकास की इस रणनीति में निम्नलिखित तथ्यों को प्राथमिकता दी गई:-

- कृषकों के हितों की रक्षा
- कृषि साख की मात्रा में वृद्धि
- भूमि संबंधी सुधारों का सुदृढ़ीकरण
- ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि।

बाजारी सुधारों का चरण (1991 के उपरांत):

- कृषि साख प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
- कृषि में मूल्य वर्धन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन
- कृषि का विविधीकरण या फसल चक्र
- कृषि आधारित निर्यातों को बढ़ावा
- मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति
- न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा अधिग्रहण मूल्य को तार्किक बनाकर किसानों को मूल्य सुरक्षा
- कृषि आधारित उद्योगों का विकास
- कृषि उत्पादों के विपरण के लिए बाजारों का विस्तार एवं संस्थागत सुधार।

Thank You